

12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% काम पूरा : गडकरी कोटा-दरा टनल से निरीक्षण के दौरान बोले केंद्रीय मंत्री हाईवे सिर्फ सड़क नहीं, विकास की नई धुरी; राजस्थान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स का भी किया ऐलान



भीलवाड़ा फोकस @ कोटा।

गर्वित । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने राजस्थान पहुंचे। उन्होंने बूंदी के लबान इंटरचेंज से कोटा की दरा टनल तक करीब 90 किलोमीटर लंबे हिस्से का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह केवल यात्रा का समय कम करने वाला हाईवे नहीं, बल्कि जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता है वहां विकास की नई संभावनाएं लेकर आएगा। उनके अनुसार एक्सप्रेसवे के आसपास उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज और कृषि आधारित उद्योग विकसित होंगे, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने राजस्थान के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि कोटा से इटावा तक बनने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल एक्सप्रेस हाईवे होगा। पहले इसे



चंबल एक्सप्रेस हाईवे के नाम से जाना जाता था। करीब 15 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है और जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समानांतर विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर इशारा करते हुए गडकरी ने कहा कि 'मुख्यमंत्री मांगते-मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते-देते नहीं थकूंगा। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, पैसे की कोई कमी नहीं है।' उन्होंने कहा कि यदि परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग के दायरे में

होगी तो उसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार राजस्थान आने पर वे राज्य के लिए बड़े पैमाने पर नई सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति देंगे। इससे पहले अलवर के पिना रेस्ट एरिया में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पुलिस अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर नियमित गश्त बढ़ाने तथा मनमाने ढंग से ट्रकों की पार्किंग रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया।



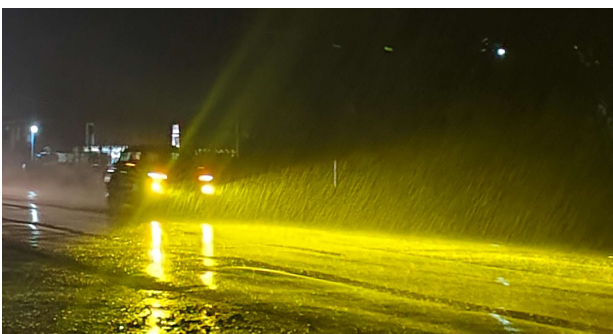
मंदिर में शिवलिंग खंडित मिलने से आक्रोश, श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी; पुलिस ने शुरु की जांच

भीलवाड़ा फोकस @ भीलवाड़ा।

शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित गायत्री नगर के कानून के बालाजी मंदिर में बुधवार को शिवलिंग खंडित मिलने से श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्र हो गए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, जांच शुरू की तथा एहतियात के तौर पर मंदिर परिसर और आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह मंदिर में नियमित रूप से दर्शन-पूजन हो रहा था। श्रद्धालु सुबह करीब नौ बजे दर्शन करने पहुंचे थे और उस समय शिवलिंग पूरी तरह सुरक्षित था। कुछ समय बाद अन्य श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर देखा तो शिवलिंग खंडित अवस्था में मिला। सूचना फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचने लगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की

मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन कैमरों के सिस्टम वाले रूम पर ताला लगा होने के कारण तत्काल फुटेज नहीं देखे जा सके। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। बाद में पुलिस ने संबंधित फुटेज सुरक्षित करने और उनकी जांच की प्रक्रिया शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया पुलिस जाबते के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।

सवाईपुर क्षेत्र में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत



भीलवाड़ा फोकस @ सवाईपुर।

(सांवर वैष्णव) कस्बे सहित बड़ला, बनकाखेड़ा, ढेलाणा, सोपुरा जाटों का, सालरिया एवं आसपास के गांवों में बुधवार रात हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दिनभर तेज गर्मी और उमस के कारण लोग परेशान रहे। रात को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवा के

साथ मुसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक तेज बारिश का दौर चला, जिसके बाद भी गरज-चमक के साथ रुक-रुक कर बारिश होती रही। बारिश के चलते गांव की गलियों और सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं मौसम सुहावना होने से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। किसानों ने भी बारिश को खरीफ फसलों के लिए लाभदायक बताया।

अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी पीएम ई-बस, बड़ा हादसा टला



भीलवाड़ा फोकस @ सवाईपुर।

(सांवर वैष्णव) क्षेत्र के बनकाखेड़ा गांव के पास बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। घटना के दौरान बस में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बनकाखेड़ा और ढेलाणा के बीच हुआ,

जब बस अचानक चालक का नियंत्रण खोने से सड़क से नीचे उतर गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बस पलटने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।

जैन समाज के मुक्तिधाम में दिनदहाड़े चोरी

भीलवाड़ा फोकस @ आसींद।

भेरूखेड़ा मार्ग स्थित जैन समाज के मुक्तिधाम में बुधवार दोपहर अज्ञात चोर पीछे की दीवार फांदकर कमरे में घुसे और बक्से का ताला तोड़कर कपड़े चोरी कर ले गए। मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष पारसमल जैन ने शाम को मौके पर पहुंचने पर चोरी

का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पारसमल जैन ने बताया कि मुक्तिधाम में पहले भी कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है।

राजस्थान में वाणिज्यिक कर विभाग की फेसलेस स्कूटनी व्यवस्था लागू

रैंडम कंप्यूटर प्रणाली से होगा मामलों का चयन, करदाताओं को पोर्टल पर ऑनलाइन देनी होगी जानकारी

भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर।

राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फेसलेस एवं रैंडमाइज्ड स्कूटनी व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था देश में अपनी तरह की अग्रणी पहल मानी जा रही है। नई व्यवस्था के तहत कर विवरणों की स्कूटनी के लिए मामलों का चयन और अधिकारियों को आवंटन पूरी तरह कंप्यूटर आधारित रैंडम प्रणाली से किया जाएगा। साथ ही पूरी स्कूटनी प्रक्रिया फेसलेस माध्यम से संचालित होगी, जिससे करदाताओं और विभागीय अधिकारियों के बीच अनावश्यक



प्रत्यक्ष संपर्क कम होगा तथा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगी।

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लंबित स्कूटनी प्रकरणों का रैंडम आधार पर आवंटन

भी कर दिया है। जिन करदाताओं के मामले स्कूटनी के लिए चयनित किए गए हैं, उन्हें विभागीय पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सूचना भेजी जाएगी। निर्धारित समय में आवश्यक कार्रवाई नहीं करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे विभागीय पोर्टल पर जारी नोटिसों और सूचनाओं की नियमित रूप से जांच करें तथा मांगी गई जानकारी और दस्तावेज निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। इससे स्कूटनी प्रक्रिया का समयबद्ध और सुगम निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा।

नर्मदा जल विवाद का ऐतिहासिक समाधान, राजस्थान को मिलेगा बड़ा जल लाभ

चार राज्यों के बीच वन-टाइम सेटलमेंट पर समझौता, पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी के जल संकट के समाधान की दिशा में बड़ा कदम

भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर।

राजस्थान के लिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के मार्गदर्शन और पड़ोसी राज्यों के सहयोग से पहले पार्वती कालीसिंध चम्बल (एमपीकेसी) परियोजना तथा हथिणीकुंड बैराज के जल उपयोग को लेकर हुए समझौतों के बाद अब नर्मदा जल विवाद के दशकों पुराने मुद्दे का भी समाधान हो गया है। इससे प्रदेश के जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता बढ़ाने के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री अमित शाह स्क्रिड्ड की मौजूदगी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा अवार्ड से जुड़े लंबित भुगतान के अंतिम निपटारे (वन-टाइम सेटलमेंट) पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस



अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अन्य तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत में राज्यों की हिस्सेदारी से जुड़े वर्षों पुराने विवाद का स्थायी समाधान माना जा रहा है। चारों राज्यों की सहभागिता और सहकारी संवाद की भावना से नर्मदा नदी के लंबित मुद्दों का समाधान संभव हो सका

है, जिससे भविष्य में नदी के जल का अधिक प्रभावी और समन्वित उपयोग किया जा सकेगा। वर्ष 1979 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण के अवार्ड के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल आवंटन तय किया गया था। अवार्ड के प्रावधानों के अनुसार मानसून के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग संबंधित राज्य अपने क्षेत्र में कर सकता है और यह जल

उसके निर्धारित हिस्से में नहीं जोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार अब मानसून के दौरान मिलने वाले अधिशेष जल के भंडारण के लिए वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के अनुरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करा रही है। इसके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान सहित जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार होगा।

